भारत- इराक संबंध

राजनीतिक संबंध : भारत और इराक के बीच पूर्णरूपेण दीर्घकालिक राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। बसरा अरब के देशों के लिए कपड़ा, मसाला, खाधान्न और अन्य उपयोगी वस्तुओं सहित भारतीय वस्तुओं का ही नहीं बल्कि प्रसिद्ध मोती के व्यापार वाला सर्वोत्कृष्ट बाजार है जो मुख्यत: भारतीय व्यापारियों एवं जौहरियों के माध्यम से फल-फूल रहा है। ब्रिटिश भारत के रेलवे कामगारों और भारतीय सैनिकों ने औपनिवेशिक युग के दौरान इस क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने में प्रमुख भूमिका अदा की थी और इन्होंने इस क्षेत्र में अपनी इस कदर छवि बनाई है कि ईराक के अनेक लोग अभी भी भारतीय नृजातीय वंश से स्वयं का सम्बद्ध होने का गौरव महसूस करते हैं। भारत और इराक ने कृषि पद्धतियों को भी साझा किया है। भारत से हारून अल राशिद द्वारा दक्षिणी इराकी जैम्स नस्ल अथवा पनभैंसा लाया गया था। इराक के दार्शनिक और सूफी संत जैसे हसन अल बासरी, जुनैद अल बगदादी और शेख बहलूल का भारत के आध्यात्मिक आंदोलनों पर इतना प्रभाव पड़ा था कि गुरू नानकदेव ने व्यक्तिगत रूप से बगदाद जाकर शेख बहलूल के साथ सात्विक और ज्ञानमीमांसा संबंधी जिज्ञासाओं के बारे में चिंतन-मनन किया। शेख बहलूल ने उन्हें लगभग तीन महीने तक अपना अतिथि बनाकर रखा। इरान के आध्यात्मिक नेता शेख शैय्यद अब्दुल कादिर जीलानी का भारत में काफी अनुचर हैं जहां उन्हें दस्तागिर साहेब या घोस-अल-आजम के नाम से जाना जाता है। दूसरी ओर, भारतीय लोग करबला पर इस्लाम के आदियुगीन शहादत के विरासत के सराय खानों और मकबरों का संरक्षण करने में सबसे आगे रहे। प्रतिवर्ष हजारों भारतीय करबला में इमाम हुसैन और इमाम अब्बास के मकबरों और अब्दुल कादिर जीलानी के मकबरों का भी दर्शन करते हैं।

भारत और इराक का एक दूसरे के सामर्थ्य के प्रति परस्पर आदर है। इराक में विरले ही ऐसा कोई विश्वविद्यालय है जिसके कुछ विधाओं की पढ़ाई भारत में नहीं होती है। चिकित्सा एवं इंजीनियरी के क्षेत्रों में अकादमिक कार्मिक सम्बद्धता पूर्णरूपेण जीवंत रही है। इराक में युद्ध छिड़ने के समय से भारत आजाद, प्रजातांत्रिक, अनेकत्ववादी, संघीय और एकीकृत इराक के निर्माण में अपना समर्थन देता रहा है। भारत ने राहत एवं आर्थिक पुनर्संरचना के कार्य में इराक की अत्यावश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से और संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में अंतरराष्ट्रीय प्रयासों के रूप में पूरा करता रहा है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की अत्यंत महत्वपूर्ण अपील के प्रत्युत्तर में, भारत ने इराक के लोगों को सहायता प्रदान करने हेतु 20 मिलियन अमरीकी डालर की प्रतिबद्धता व्यक्त की। इस प्रतिबद्धता के तहत किए जाने वाले कार्यकलापों में विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से दूध के पावडर की आपूर्ति करना, राजनय में विदेश सेवा के अधिकारियों और अन्य इराकी अधिकारियों को सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में

प्रशिक्षण देना शामिल है। डब्ल्यू एफ पी के सहयोग से, भारत ने सीरिया में इराकी शरणार्थियों एवं इराक के विद्यालय के छात्रों को पुष्ट बिस्कुटें प्रदान कीं। इसके अलावा, भारत ने इराक में निवेश, पुनर्संरचना एवं विकास हेतु इराक के अंतरराष्ट्रीय पुनर्संरचना निधि संकाय (आई आर एफ एफ आई) को 10 मिलियन अमरीकी डॉलर का सहयोग किया।

क्षमता निर्माण के संदर्भ में, भारत ने इराक सरकार के कर्मचारियों को भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (आई टी ई सी) के तहत 80 स्लॉट प्रतिवर्ष देता रहा है। वर्तमान वर्ष के लिए आई टी ई सी कार्यक्रम के तहत 70 स्लाटों का आवंटन किया गया है। भारत भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आई सी सी आर) के द्वारा आयोजित 'सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम छात्रवृत्ति योजना' (सी ई पी) तथा 'सामान्य सांस्कृतिक छात्रवृत्ति योजना' (जी सी एस एस) के तहत भारत में उच्च अध्ययन करने हेतु इराक के छात्रों को प्रतिवर्ष 80 स्लॉट प्रदान करता रहा है।

भारतीय तेल निगम लिमिटेड (आई ओ सी) ने डाउन स्ट्रीम तेल सेक्टर से संबद्ध विभिन्न विषयों में इराक के तेल अधिकारियों को भारत में प्रशिक्षण प्रदान किया है। अब तक इराक के तेल मंत्रालय के 220 से अधिक कार्मिकों ने आई ओ सी के 20 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का लाभ उठाया है।

आम जनता तथा संस्थाओं के बीच परस्पर संबंध इतने घनिष्ठ हैं कि आज, इराक के लोगों द्वारा गुणवत्ता चिकित्सा इलाज कराने के लिए भारत एक सर्वाधिक पसंदीदा स्थान बन गया है। कम से कम 75 इराकी रोगी अपने चिकित्सीय इलाज हेतु दैनिक आधार पर भारत की यात्रा करते हैं। इराक के सैकड़ों लोग स्व-वित्तपोषण आधार पर उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अपने बच्चों को भारत भेजना चाहते हैं।

मिशन फिलहाल प्रतिदिन लगभग 150-200 वीजा जारी कर रहा है, जिनकी संख्या गर्मी के दिनों में बढ़कर 350 हो जाती है। अधिकांश यात्री चिकित्सा, शिक्षा और व्यवसाय के प्रयोजनों से भारत का दौरा करते हैं। पिछले वर्ष, लगभग 2800 छात्रों को वीजा जारी किए गए थे और यह अनुमान लगाया गया है कि भारत में लगभग 100000 से अधिक इराकी छात्र हैं। कैलेंडर वर्ष 2014 में, मिशन ने 43474 वीजा जारी किए।

दोनों देशों के बीच उच्च स्तर पर राजनीतिक आदान-प्रदान होता रहा है। ईराक के ऊर्जा कार्य उप प्रधानमंत्री हुसैन अल शरिस्तानी ने संयुक्त आयोग की बैठक की अपने तत्कालीन तेल मंत्री की

हैसियत से अध्यक्षता करने हेतु मई 2007 में भारत का दौरा किया। इराक के व्यापार मंत्रालय से 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने फरवरी, 2009 में भारत का दौरा किया। उद्योग तथा खनिज मंत्री श्री फौजी फ्रांसों हरीरी ने फरवरी, 2009 में कार्मिकों, व्यावसायियों और उद्यमियों के 20 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष के रूप में भारत का दौरा किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री समरराय ने अप्रैल 2011 में दिल्ली एवं बंगलुरू का दौरा किया। इराक के नगर निगम एवं जनकार्य मंत्री आदिल मुहेदार राजी अल मालिकी ने भारतीय उद्योग के साथ सी आई आई द्वारा आयोजित परस्पर संवाद में भाग लेने के लिए नवंबर, 2011 में दिल्ली का दौरा किया। उप प्रधानमंत्री, श्री राउस्च शॉवेज ने व्यापार मंत्री, डॉ. खैराल्ला हसन बाबाकेर, राष्ट्रीय निवेश अध्यक्ष, डॉ. सैमी आरजि और वरिष्ठ इराकी अधिकारियों के साथ भारतीय उद्योग परिसंघ (सी आई आई) के आमंत्रण पर दोनों देशों के बीच व्यापार एवं आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए फरवरी, 2012 में भारत का दौरा किया। उप प्रधानमंत्री ने सी आई एम श्री आनंद शर्मा, एम पी एन जी श्री जयपाल रेड्डी और योजना आयोग के उपाध्यक्ष, श्री मोंटेक सिंह अहलुवालिया से भी मुलाकात की। उप प्रधानमंत्री, श्री राउस्च शॉवेज ने व्यापार मंत्री, डॉ. खैराल्ला हसन बाबाकेर, राष्ट्रीय निवेश अध्यक्ष, डॉ. सैमी आरजि और वरिष्ठ दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल ने 300 से अधिक भारतीय कंपनियों के साथ परस्पर वार्ता की जबकि मुंबई एवं चेन्नै प्रत्येक स्थान पर, इस परस्पर वार्ता के दौरान 200 दूसरी कंपनियां उपस्थित थीं। श्री उसामा अली नुजाफी, इराकी प्रतिनिधि परिषद के अध्यक्ष ने 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ माननीय लोक सभा अध्यक्षा, सुश्री मीरा कुमार के आमंत्रण पर 15 - 19 दिसंबर, 2012 के दौरान भारत का दौरा किया। के आमंत्रण पर दोनों देशों के बीच व्यापार एवं आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए फरवरी, 2012 में भारत का दौरा किया। इस प्रतिनिधिमंडल ने उप राष्ट्रपति एवं राज्य सभा के अध्यक्ष हामिद अंसारी और विदेशमंत्री, श्री सलमान खुर्शीद से मुलाकात की। लोक सभा अध्यक्षा, सुश्री मीरा कुमार के साथ औपचारिक प्रतिनिधिमंडलीय स्तरीय वार्ताएं की। श्री फालीह अल फैरूयाध, इराक के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने 17 - 21 दिसंबर, 2013 की अवधि के दौरान भारत का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री, विदेश मंत्री तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से बैठकें कीं और इराक एवं भारत के बीच द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग से संबंधित मामलों और इसे करने के उपायों के बारे में चर्चा की। इस दौरे के दौरान रक्षा अध्ययन संस्थान (नई दिल्ली) और रणनीतिक अध्ययनों हेतु अल नहराइन केंद्र (बगदाद) के बीच सहयोग के बारे में एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके पहले, भारतीय उद्योग परिसंघ (सी आई आई) के द्वारा प्रायोजित एक 16 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल, जिनमें विभिन्न भारतीय उद्योगों के प्रतिनिधि शामिल थे, ने अक्टूबर, 2011 में भारत का दौरा किया। इराक सरकार के राष्ट्रीय निवेश आयोग ने इस प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी की। इस प्रतिनिधिमंडल ने इराक के दो उप प्रधानमंत्रियों, नगर निगममंत्री और तेल

उद्योग के सरकारी उपक्रमों के प्रमुखों से मुलाकात की। इस सफल दौरे ने इराक की अर्थव्यवस्था तथा भारतीय निवेश को स्वागत करने में इराक की उत्सुकता और इराक की विशेषज्ञता को विकसित करने एवं इसके लिए योगदान करने में भारतीय उद्योग की सक्षमता को परिलक्षित किया।

माननीय विदेश मंत्री श्री सलमान खुर्शीद ने 19 - 20 जून, 2013 के दौरान इराक का दौरा किया। वर्ष 1990 के बाद से भारत के किसी विदेश मंत्री का इराक के लिए यह पहला दौरा था। विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नौरी अल मलिकी, उप प्रधानमंत्री श्री हुसैन अल शाहरिस्तानी, प्रतिनिधि परिषद के अध्यक्ष श्री उसामा अल नुजायफी से मुलाकात की तथा विदेश मंत्री श्री होशयार जेबारी से प्रतिनिधिमंडल स्तर पर बातचीत की। बैठकों के दौरान वरिष्ठ राजनीतिक स्तर पर द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ बनाने पर सहमति व्यक्त की गई। इस बात पर भी सहमति व्यक्त की गई कि गहन संबंध को रणनीतिक भागीदारियों में से एक के रूप में प्राथमिकता दी जाए और विशेषकर रिफाइनरी, पेट्रोरसायन, खाद्य, संयंत्रों इत्यादि जैसी प्रमुख परियोजनाओं में एक दूसरे की अर्थव्यवस्था में सक्रिय रूप से सहयोग किया जाए। प्रतिनिधि परिषद के अध्यक्ष, श्री उसामा अल नौजायफी ने यह भी सूचित किया कि इराक भारत मित्रता फोरम का गठन प्रतिनिधि परिषद, जिसमें प्रतिनिधि परिषद के सदस्य सुश्री अला तलाबानी की अध्यक्षता में राजनीतिक स्पेक्ट्रम के सभी सेक्शन शामिल हैं, में किया गया है।

डॉ. वीरप्पा मोइली, माननीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री संयुक्त आयोग की बैठक, जो बगदाद में जुलाई, 2013 में आयोजित की गई थी, में भाग लेने के लिए एक 25 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई की। डॉ. मोइली ने इराक के प्रधानमंत्री मलिकी, उप प्रधान मंत्री डॉ. सलेह अल मुल्लक से भी मुलाकात की और तेल मंत्री, डॉ. अब्दुल करीम लुआएबी से गहन बातचीत की।

भारत से एक 12 सदस्यीय फिक्की प्रतिनिधिमंडल, चावल एवं सुगर के निर्यातक शामिल हैं, ने इराक के व्यापार मंत्रालय तथा अन्य संगठनों के साथ समझौता वार्ता हेतु 9 - 10 मार्च, 2010 के दौरान इराक का दौरा किया। व्यापार मंत्रालय 120000 मीट्रिक टन बासमती चावल (लगभग 150 मिलियन अमरीकी डॉलर) तथा 25000 मीट्रिक टन चीनी (लगभग 15 मिलियन अमरीकी डॉलर) का क्रयादेश दे रहा है, यह इराक के व्यापार मंत्री ने दौरे पर आए व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल के साथ सीधे समझौते के माध्यम से तत्क्षण दिया गया पहला क्रयादेश था।

इराक के प्रधानमंत्री श्री नौरीअल मालिकी ने अगस्त 2013 में भारत में सरकारी दौरा किया।

प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता एवं विचार विमर्श करने के अलावा, उन्होंने माननीय राष्ट्रपति, माननीय उप राष्ट्रपति से मुलाकात की और आगरा एवं मुंबई का भी दौरा किया। उन्होंने फिक्की, आई सी सी एवं एसोचम द्वारा आयोजित संयुक्त व्यवसाय समारोह में भी भाग लिया। प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान चार समझौता ज्ञापनों जिनमें एक ऊर्जा सेक्टर में सहयोग, एम ई ए एवं एम आई ए के बीच सहयोग, दोनों मंत्रालयों के एफ एस आई के बीच सहयोग और जल स्रोत प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन शामिल हैं, पर हस्ताक्षर किए गए। उनके साथ एक बहुत बड़ा प्रतिनिधिमंडल भी साथ आया था जिसमें इराक के तेल मंत्री, कृषि मंत्री एवं प्रमुख व्यावसायिक शामिल थे।

वाणिज्यिक संबंध : भारत और इराक के बीच आर्थिक एवं व्यापारिक संबंध मार्च 2003 में इराक पर हुए आक्रमण के बाद कमी आई। भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति करने वाले देशों में इराक का स्थान दूसरा, सऊदी अरब के बाद और ईरान से पहले है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इराक से कच्चा तेल का अकेला सबसे बड़ा क्रेता देश भी है जो लगभग 250000 इराकी कच्चे तेल का प्रापण करता है। वर्ष 2013 -14 में, ऐसा अनुमान है कि भारत 18 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक मूल्य का कच्चा तेल का आयात करता था। एच पी सी एल और बी पी सी एल इराक से कच्चा तेल आयात करने वाली अन्य दो प्रमुख कंपनियां हैं। भारत थोक मात्रा में कच्चे तेल का आयात करने के अलावा, इराक से कच्चा ऊन एवं गंधक जैसी वस्तुओं का भी कम मात्रा में आयात करता है। 2014 -15 में भारत और इराक के बीच व्यापार 15 बिलियन अमरीकी डालर था जिसमें भारत की और से इराक को किए गए निर्यात का मूल्य 829.32 मिलियन अमरीकी डालर था और इराक से भारत द्वारा आयात का मूल्य 14.24 बिलियन अमरीकी डालर के आसपास था। भारत द्वारा इराक को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में अनाज, लोहा और इस्पात, मांस और मांस उत्पादों, औषधीय वस्तुएं, कृषि रासायनिक पदार्थ, प्रसाधन की वस्तुएं, रबर के विनिर्मित उत्पाद, पेंट, रत्न एवं आभूषण, चीनी मिट्टी के बर्तन, धातु से विनिर्मित उत्पाद, मशीनी उपकरण, विद्युत यंत्र एवं औजार, परिवहन अपस्कर, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, हस्तकला, चीनी, चाय, पोशाक शामिल हैं। दुबई के माध्यम से भी बहुत अधिक मात्रा में निर्यात होता है। इराक से भारत द्वारा जिन वस्तुओं का आयात किया जाता है उसमें खनिज ईंधन की बहुतायत है तथा कम मात्रा में गिरी, कच्ची खाल एवं स्किन तथा ऊन का भी आयात किया जाता है।

इराक भारतीय कंपनियों के लिए सबसे बड़ा परियोजना निर्यात लक्ष्य रहा है। तथापि, यहां भारतीय कंपनियों की विद्यमानता कम रही है। मैसर्स शपूरजी पॉल्लोनजी ने बसराह में होटल के पुनर्निर्माण संबंधी 85 मिलियन अमरीकी डॉलर की संविदा प्राप्त की है और मैसर्स लान्सो

इंफ्राटेक ने आकाज पावर परियोजना के निर्माण संबंधी 81 मिलियन अमरीकी ई पी सी की संविदा प्राप्त की है। टाटा स्टील ने इराक में अपने बैजी शुष्क गैस परियोजना के लिए 110 किलोमीटर पाइप लाइन लेप की आपूर्ति हेतु कोरियन गैस कॉरपोरेशन (कोगैस) के साथ एक कई मिलियन पौंड के क्रयादेश की घोषणा की है।

भारतीय समुदाय : भारतीय मूल के कुछ परिवार मुख्यत: नजफ, करबला, बसरा एवं बगदाद जैसे पवित्र शहरों में रहते हैं। भारतीयों का इराक के लिए यात्रा के विरूद्ध भारत सरकार के भारतीय परामर्शी प्रतिबंध, जो वर्ष 2004 से दिनांक 03.05.2010 तक लागू था, को समाप्त करने के बाद भारतीय कामगारों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक विकसित एवं शांत कुर्दिस्तान क्षेत्र, जिसमें इरबिल, सुलेमानिया एवं दोहक गार्वनेटों में निरंतर बढ़ी है और उन्हें इस्पात के मिलों, तेल की कंपनियों एवं निर्माण परियोजनाओं में बहुत अच्छा वेतन मिल रहा है और वहां कार्य करने की स्थितियां काफी बेहतर हैं। के आर जी में भारतीय व्यक्तियों की संख्या अनुमानत: 15000 के करीब है। इसी कारण से, भारतीय कंपनियों जैसे रिलायंस, जिंदल, अजंता, इलेक्ट्रोथर्म, इत्यादि ने भी के आर जी में अपना व्यवसाय स्थापित करने का निर्णय लिया है। यदापि, इराक में आतंकी हमलों से संबंधित सुरक्षा मुद्दों और उत्तरी इराक के कुछ हिस्सों का लड़ाकुओं के कब्जे में चले जाने के मद्देनजर, इराक में कार्यरत भारतीय व्यक्तियों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं थी। राजदूतावास ने 7000 से अधिक लोगों को देश में वापस लाया जिसके लिए भारत सरकार द्वारा पूर्ण प्रत्यावर्तन व्यय का वहन किया गया। राजदूतावास ने 1000 से अधिक भारतीय कामकारों को अपेक्षित यात्रा दस्तावेज मुहैया कराते हुए उनकी कंपनियों से वापस बुलाने में सहायता भी की। वर्तमान में, इराक के विभिन्न हिस्सों में रह रहे भारतीयों की संख्या लगभग इस प्रकार है : कुर्दिस्तान: 7000-8000; बसरा : 2500-3000; बगदाद : 500; नजफ / कर्बला / हिल्ला : 1000-1500

उपयोगी संसाधन :

भारत का राजदूतावास, बगदाद की वेबसाइट :

http://indianembassybaghdad.in

भारत का राजदूतावास, बगदाद फेसबुक पेज :

https://www.facebook.com/IndiainIraq

***

जून, 2015